कोविड के समय में भूमि अधिकार एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ANGOC का कथन

कोरोना वाइरस वैश्विक महामारी ने मानव के रूप में हमारी कई अंतर्निहित कमजोरियों और जोखिमों को उजागर किया है। इनमें व्यापक असमानता, हृदयहीन अर्थव्यवस्था, पर्यावरण का विनाश, भूमि का अन्यायपूर्ण वितरण, आश्रय और आजीविका की कमी, बढ़ता प्रदूषण और भीड़भाड़ वाले शहरों के लिए प्राकृतिक संसाधन, भोजन की कमी और पोषण की पहुंच, सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल की अनुपस्थिति, पृथ्वी का बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसे बुनियादी सवाल उठते हैं ।

इस बीच, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, प्राकृतिक आवासों का क्षरण और विखंडन, पशुओं, प्रजातियों और पौधों का व्यापार, मानवजनित जलवायु परिवर्तन - नई बीमारियों के उद्भव के रास्ते बनाते हैं। अधिकांश वैश्विक महामारियां जानवरों से मनुष्यों में होने वाले रोगों के संचरण से पैदा हुई हैं। खेती और वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रास्ता साफ करने के लिए जंगलों को साफ किया गया है।

जैसा कि वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोविड के लिए इलाज खोजने की, अर्थशास्त्रियों के लिए टीके लगाने की कोशिश की, और राजनीतिक नेताओं ने महामारी से लड़ने की तैयारियां की है, और सामान्य जनमानस ने अब कोरोना के साथ रहना सीख लिया है। इस साल मार्च से, सरकारों ने इस महामारी ने निपटने की कोशिश भी की है जिनमें सामाजिक दूरी उपाय, यात्रा प्रतिबंध, कर्फ्यू, लॉकडाउन और सामुदायिक क्वारन्टीन व्यवस्था प्रमुख हैं।

फिर भी जब कोविड स्वास्थ्य संकट के रूप में शुरू हुआ, तो वर्तमान घटनाओं के अनुरूप इस महामारी ने गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के संकट पैदा किये हैं। मजदूर, भूमिहीन लोग और झुग्गी-झोपड़ी के लोगों पर इसका असर पड़ा है।

कोरोना वायरस के प्रकोप के पूर्व दुनिया भर में अनुमानित 821 मिलियन लोग पहले से ही कुपोषण से जूझ रहे थे। अधिकांशतः कम आय वाले देशों में रहने वाले दुनिया के अधिकांश भूखे लोगों की आबादी वर्ष 2018 में 12.9% थी।

खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं और बाजारों में महामारी की वजह से हुए व्यवधानों से खाद्य प्रणाली सीधे प्रभावित हुई है। इसी समय, नौकरियों के नुकसान के परिणामस्वरूप भोजन का उत्पादन और वितरित करने की क्षमता बाधित हुई है। साथ ही इससे लोगों की क्रय शक्ति में कमी आती है, खासकर उन लोगों में जो कि गरीब और कमजोर हैं।

भूमि, बाज़ार और संसाधन तक पहुँच के बिना, किसानों की आजीविका सुरक्षा कम हुई है। ऐसे निर्माता जो अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि कार्यों पर निर्भर थे, यात्रा प्रतिबंधों की वजह से रोजगार पाने में अक्षम हैं। राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और व्यापार और यात्रा पर प्रतिबंध की वजह से खाद्य श्रृंखला बाधित हुई है जिसकी वजह से एशिया भर में छोटे किसानों की आजीविका अपंग हो गई है। इन देशों में जहां कृषि अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

जैसा कि सरकारें वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को घर में रहने के लिए कहती हैं, सुरक्षित भूमि की आवश्यकता और आवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी के लिए महत्वपूर्ण हो गया है, जैसा पहले कभी नहीं था। परिवहन पर प्रतिबंध के साथ, दैनिक दिहाड़ी मजदूर और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक अपनी आय खो रहे हैं, और कईयों को काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कानूनी समझ की कमी और मकान के किराए का भुगतान करने में असमर्थता के कारण सबसे कमजोर लोग बेघर हैं और प्रवासी श्रमिक, जो शहरों में नौकरियों के नुकसान के साथ, अपने गाँवों में लौटने के लिए मजबूर हो गए हैं। लोग अपने परिवार के साथ रहने के लिए सैकड़ों

किलोमीटर पैदल चल पड़े थे। भारत, जहाँ की आबादी 1.3 अरब है, बड़े शहरों में फँसे हुए मजदूर मजबूरी में अपने गाँवों की ओर लंबे सफर पर निकल पड़े।

शहरी गरीबों पर सबसे ज्यादा प्रभाव- जो गरीब काम में कार्यकाल की सुरक्षा के बिना रहते हैं, आवास में अपर्याप्त वातानुकूलन, स्वच्छता जैसे अभाव के साथ ही महामारी के प्रकोप होने पर इनको मेजबान समुदायों द्वारा कलंकित और बेदखल किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच, और उनकी नौकरी की सुरक्षा की कमी उन्हें खाद्य कीमतों में बढोत्तरी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। पौष्टिक भोजन की कमी से संक्रमण और रुग्णता के प्रति उनकी भेद्यता बढ़ जाती है।

गरीब, बुजुर्ग, महिलाओं, और बच्चों के कमजोर समूह न केवल संक्रमित होने के अधिक जोखिम का सामना करते है बल्कि इनमें कुछ क्षेत्रों में कम ध्यान दिया जाता है। सरकार के लिए प्राथमिकताओं के बीच प्रतिस्पर्धा, स्वास्थ्य देखभाल और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। भारत में, स्कूलों के बंद होने के कारण 120 मिलियन से अधिक बच्चों ने अपने मिड-डे मील के तहत मिलने वाले भोजन तक पहुंच खो दी है। घरेलू दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ी हैं क्योंकि महिलाएं और बच्चे घर पर अधिक समय बिताते है क्वॉरेंटाइन नियमों की वजह से उनका बाहर निकलना कम हो गया है।

पहले से ही इस बात की चर्चा है कि वैश्विक महामारी से आर्थिक गिरावट और भी बढ़ सकती है वैश्विक गरीबी के रूप में आधे अरब से अधिक लोगों, या कुल मानव आबादी का आठ प्रतिशत हो सकते हैं। 1990 के बाद पहली बार तीन दशकों में वैश्विक स्तर पर गरीबी बढ़ेगी।

सरकारों ने अल्पकालिक सामाजिक अमलीकरण कार्यक्रम में गरीबों के लिए सुरक्षा और कारपोरेट को भी सहायता दी है। फिर भी जब तक कि विकास मॉडल में भारी बदलाव नहीं होता है जो लोग और समुदाय केंद्र में रहेंगे।

हालांकि ये भोजन और नकद वितरण कार्यक्रम तत्काल भूख को कम करते हैं, लंबे समय की भूख के लिए कुछ समाधान नहीं देते हैं। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ये स्थायी हैं लंबे समय के, और क्या वे गरीब लोगों को पुरानी गरीबी, भूख और से बचने के लिए सशक्त बनाते हैं। पहले से ही, तंग बजट वाले विकासशील देशों ने विदेशी ऋण का सहारा लिया है बढ़ते हुए राष्ट्रीय ऋणों को हमारे बच्चों को वहन करना होगा। इसके अलावा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इन कोरोनावायरस प्रतिक्रिया कार्यक्रमों में भ्रष्टाचार भी हो रहा है।

सरकारों की बदलती प्राथमिकताओं और ध्यान के साथ, कुछ व्यक्तियों और समूहों भी सक्रिय हो गए हैं जो अवैध कटाई, अवैध खनन और भूस्खलन के माध्यम से स्थिति का लाभ लेना चाहते हैं। फिलीपींस में ही तालाबंदी के बाद कम से कम चार अवैध खनन गतिविधियों की शुरुआत हुई है।

एशिया भर के छोटे किसान इस महामारी की सुर्खियों में बने हुए हैं। ये प्रमुख रूप से अनाज, दालें, सब्जियाँ, और समुद्री भोजन की मांग को पूरा कर रहे हैं। फिर भी छोटे किसानों उत्पादकों, ग्रामीण कारीगर और स्वदेशी लोगों को उत्पादक संसाधनों (यानी, भूमि) पर पहुंच और नियंत्रण से वंचित रखा जाता है। (पानी, जंगल और समुद्र तट) जिस पर वे आजीविका के लिए निर्भर हैं।

खाद्य उद्योग में बढ़ते कॉर्पोरेट नियंत्रण ने एशिया के छोटे किसान की स्थिति को और जटिल कर दिया है। किसानों को बाधाओं की एक नई परत का सामना करना पड़ रहा है - सेवाओं, ऋण और बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई, कमजोर विस्तार सेवाएं, और मूल्य निर्धारण नीतियां छोटे किसानों के खिलाफ काम करती हैं। किसानों की यह अलगाव प्रक्रिया कोरोना महामारी के समय उनके ऊपर एक हमले की तरह है।

राजनेताओं और राज्य के नेताओं ने इसी तरह महामारी का फायदा उठाकर अपनी शक्ति को मजबूत किया है, इससे आगे बढ़ती हैं असमानताएँ जो भूख और गरीबी का कारण बनती हैं। कई एशियाई देशों में आम नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता बढ़े हुए राज्य सैन्यीकरण और आक्रामक रूप से परेशान करने वाले उदाहरणों को इंगित करते हैं। पुलिस; असंतोष, मीडिया और मुक्त भाषण पर सरकार की कटुता। फिलीपींस में, सरकार के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को 2020 के आतंकवाद-रोधी अधिनियम के तहत धमकी दी जा रही है, जिसे हालांकि लागू नहीं किया गया है।

आज, अगर कोविड-19 ने हमें कुछ भी सिखाया है, तो यह है कि हमें अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को फिर से बनाने की जरूरत नहीं है व्यक्तियों, लेकिन सामूहिक रूप से एक समाज के रूप में भी।

दुनिया इसी तरह के संकटों के खिलाफ संघर्ष करना जारी रखेगी, लेकिन हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुनहरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए। जिनके लिए हमारे बच्चे बड़े होने पर उत्सुक हों, एक ऐसा भविष्य, जिसमें वह खुद खुशी से बड़ा होना चाहें। इस स्थिति में पहले की तरह जीवन जीने के इतर हम बेहतर बनें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार, हमें एक समतावादी, समावेशी और सतत अर्थव्यवस्था और समाज को बनाना होगा, जहाँ हमें किसी आपदा के डर न हो, न ही जलवायु परिवर्तन जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो।

विकास की रूपरेखा को ऐसे बदलना चाहिए जहाँ लोग और पर्यावरण पर प्रधानता हो। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण छोटे उत्पादकों के हाथों में होना चाहिए - सरकार का समर्थन यह सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए कि वे पर्याप्त और सुरक्षित रूप से पौष्टिक भोजन का उत्पादन करने में सक्षम हैं। स्वदेशी लोगों और वनवासियों की भूमिका जैव विविधता संरक्षण में नई बीमारियों के उद्भव और प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण रही है और इसे मान्यता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, सिर्फ आर्थिक स्थिति, उचित मजदूरी, और व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग महामारी जैसे और राज्य अवसंरचना संकटों द्वारा लाए गए अचानक आघात का सामना करने में सक्षम हो।

हमें अपने प्रतिमान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है यदि हम सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करते हैं - अर्थात, यह सुनिश्चित करना कि भोजन समान रूप से वितरित हो अन्यथा ये गरीबों और हाशिए पर पहुँचा जा सकता है। यह पर्याप्त नहीं है कि राज्य अपना ध्यान केवल वैश्विक और राष्ट्रीय मूल्य के विषय पर रखें। सरकारों को छोटे खाद्य उत्पादकों और स्थानीय खाद्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए परस्पर सहयोग करना चाहिए जिससे कि सभी के लिए भोजन सुनिश्चित किया जा सकें।

स्थायी खाद्य सुरक्षा के निर्माण के लिए मूल कार्य सिद्धांत खाद्य किलोमीटर को कम करना है "जहां भोजन का उत्पादन होता है, और जहां समान भोजन का उपभोग किया जाता है, उसके बीच की दूरी को कम करना" - संभव सीमा तक। हमें समुदाय के नेतृत्व वाले प्रतिक्रिया प्रणालियों में निवेश करने की दिशा में एक बदलाव की आवश्यकता है।

इस दृष्टिकोण से छोटे उत्पादकों के भूमि और संसाधनों पर अधिकर सुनिश्चित होंगे- हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए स्थानीय बाजारों को विकसित करने पर, जहां छोटे उत्पादकों की सीधी पहुंच हो, और जहां उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो। यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध और जवाबदेही का निर्माण करेगा, ताजा उत्पादन ग्राहक को मिलेगा और व्यापक दूरी पर भोजन के परिवहन से जुड़े कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा।

कृषि सुधार और भूमि कार्यकाल सुरक्षा राष्ट्रीय विकास रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। एशिया में निरंतर खाद्य आत्मनिर्भरता और विकास केवल अधिक न्यायसंगत भूमि के साथ हासिल किया जा सकता है

जिनमें भूमि पुनर्वितरण, समर्थन सेवाएं, कृषि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकियों, स्थायी संसाधन के साथ प्रबंधन और सामुदायिक सशक्तिकरण।
भूमि एक आर्थिक संपत्ति या वस्तु से अधिक है। भूमि तक पहुंच न केवल अस्तित्व का एक स्रोत लाता है, बल्कि मानवीय गरिमा और सुरक्षा की भावना और भूख एवं गरीबी से बाहर निकलने के अवसर को भी बढ़ाता है। भूमि का न्यायपूर्ण बंटवारा संसाधन संघर्ष और ग्रामीण बहिष्कार को कम करत है, और आर्थिक- राजनीतिक सुधार करता है। शांति स्थापित करने का रास्ता यही है।

छोटे उत्पादकों के पास अपनी भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण होना चाहिए; और आदिवासियों को भूमि अधिकार के साथ ही उनकी परम्पराओं को मान्यता एवं सम्मान दिया जाना चाहिए। ये संघर्षों में कमी सुनिश्चित करने और संसाधनों का प्रबंधन करने की दिशा में आवश्यक कदम हैं ।

रोजगार की सुरक्षा के साथ-साथ छोटे स्तर पर विविधतापूर्ण और टिकाऊ कृषि अभ्यासो की आवश्यकता है। हमारे इतिहास में, छोटे किसानों और उत्पादकों ने एशियाई कृषि की रीढ़ के रूप में काम किया है और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। एशिया दुनिया के 75% किसान परिवारों का घर है, जिनमें से 80% छोटे पैमाने पर कृषि करते हैं।

औद्योगिक कृषि से समुदाय आधारित खेती की ओर एक उल्लेखनीय बदलाव होना चाहिए। आज के समय मे ऐसे तंत्र की आवश्यकता है जो प्राकृतिक और स्थानीय आदानों का उपयोग करके पुनर्जीवन का निर्माण करते हैं - मिट्टी को पुनर्जीवित करने, फसलों को निषेचित करने, और कीटों से लड़ने के काम करते हैं। उचित जैव विविधता को बनाए रखना, कार्बन उत्सर्जन, कृषि प्रणालियों को कम करना कीटनाशकों और उर्वरकों जैसे बाहरी आदानों पर कम निर्भर होना चाहिए। इससे किसानों की भेद्यता कम होती है अचानक झटके और कीमत में उतार-चढ़ाव होता है। स्थानीय क्षेत्रीय बाजार ऐसी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक बेहतरीन उदाहरण साबित होंगे।

कार्रवाई के लिए पुकार:

- हम सुरक्षित एवं प्रभावी कोविड 19 वैक्सीन के प्रति विभिन्न देशों द्वारा की गई मांग में अपना समर्थन व्यक्त करते हैं जिसमें कोरोनावायरस वैक्सीन की सार्वभौमिक उपलब्धता, पर्याप्त उत्पादन, सभी देशों तक पहुँच, मुफ्त एवं बौद्धिक संपदा द्वारा अपरिवर्तित हो।

- हम सभी में सक्रिय सशस्त्र संघर्षों में तत्काल संघर्ष विराम के आह्वान का समर्थन करते हैं। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया के कुछ हिस्सों, राष्ट्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए उनके उपाय संघर्ष-संवेदनशील, गैर-भेदभावपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों के साथ संरेखित हैं एवं शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (आईडीपी), विकलांग लोग, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील हैं।

- जैसे ही प्रोत्साहन पैकेज लॉन्च किए जाते हैं, हम तत्काल विकासशील देश और आंतरिक संघर्षों से पीड़ित देशों में ऋण राहत और ऋण माफी करने का आह्वान करते हैं।

- दिसंबर 2019 में, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय ने 2021 में फ़ूड सिस्टम समिट की घोषणा की जिसका उद्देश्य था 2030 एसडीजी एजेंडा में खाद्य प्रणालियों के दृष्टिकोण के लाभों को अधिकतम करना, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करना, खाद्य प्रणालियों को समावेशी बनाना, और स्थायी शांति का समर्थन करना। हालांकि, जब तक कि सार्थक भागीदारी न हो और छोटे पैमाने पर खाद्य उत्पादकों द्वारा

एक प्रभावी आवाज न दी जाए, संगठन और भोजन से संबंधित अन्य नागरिक समाज की आवाज सुने बिना ऐसी कोई समिट करना व्यर्थ होगा।

राज्य की प्रतिक्रिया के लिए तत्काल कार्रवाई:

- खाद्य सहायता और आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से परे, कृषि और खाद्य प्रणालियों का प्रशासन का पुनर्गठन और रूपांतरित किया जाना चाहिए ताकि नीतियां और कार्यक्रम सीधे तौर पर छोटे किसान और उत्पादक, स्वदेशी समुदाय और शहरी गरीबों की जरूरतों का जवाब दें।

- सरकारों को महामारी के प्रभावों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय बजट में वृद्धि करते हुए की प्राथमिकताओं को स्थानांतरित करना चाहिए, गरीबों को सहयोग किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संसाधनों का उपयोग किया जाता है, प्रभावी रूप से भ्रष्टाचार को रोका जाना चाहिए। नागरिक समाज की भागीदारी और बनाए रखने के साथ निगरानी तंत्र ऐसे कार्यक्रमों के वितरण की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मीडिया की स्वतंत्रता की स्थापना की जानी चाहिए।

- सिकुड़ती लोकतांत्रिक व्यवस्था के समय में, जो इस महामारी के दौरान और सिकुड़ रहा है, सामाजिक संगठनों, भूमि और मानवाधिकार रक्षकों, और मीडिया का सम्मान और रक्षा की जानी चाहिए।

- किसानों, मछुआरों, स्वदेशी लोगों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें COVID- 19 को फैलाने से बचने में मदद करने के लिए खाद्य उत्पादन, हैंडलिंग और प्रसंस्करण में शामिल।

- खाद्य श्रृंखला में महिलाओं के स्थान को मान्यता देना और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए परस्पर सहयोग उपलब्ध कराना।

- गरीब और सबसे कमजोर लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करना और कोविड 19 संकट के बाद सभी समुदायों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- विदेश और शहरी क्षेत्रों से प्रवासियों को ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने में सहायता प्रदान करें। कोरोनापरीक्षण और सक्रिय संपर्क अनुरेखण विशेष रूप से किया जाना चाहिए।

नागरिक समाज, समुदायों और लोगों के लिए तत्काल कार्रवाई

- इस संकट के दौरान सरकार या मानवीय सहायता के अभाव में, समुदायों और नागरिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार हम इन संस्थाओं को कोविड 19 प्रतिक्रिया गतिविधियों की निगरानी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। नागरिक संस्थाओं के काम करने से किसानों और मछुआरों, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, वंचितों और कमजोर लोगों, समुदाय के साथ स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्वदेशी समुदाय, युवा और महिला समूह के बीच संवाद बना रहेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं एवं इन सभी की आवाज बुलंद होती है।

- जबकि सरकारें और मानवतावादी संस्थान नई और अधिक प्राथमिकताओं पर अपने प्रयासों को केंद्रित करते हैं, हम नागरिक संस्थाओं को उन राज्य संस्थानों के प्रति सतर्क रहना चाहिए जो महामारी का उपयोग करते हैं मानवाधिकार मानकों की परवाह किए बिना भूमि, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर

उनका नियंत्रण करते हैं और व्यावसायिक मुनाफा कमाते हैं। हम भूमि संघर्ष के मामलों की निगरानी करना जारी रखेंगे, विशेष रूप से वहां जहां वे होते हैं, भूमि पर जबरदस्ती कब्जे की घटनायें होती हों।

- हम समुदायों एवं सोशल मीडिया पर लोगों और व्यक्तियों के खिलाफ जाति, राष्ट्रीयता, रंग, लिंग, धर्म, जाति और सामाजिक वर्ग के आधार पर फैलने वाली अफवाहों, पूर्वाग्रह और भेदभाव को रोकने के लिए नागरिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करते हैं। जब वायरल संक्रमण या रोग फैलते हैं, तो दोष के लक्ष्य आमतौर पर उन होते हैं जो लोग नस्लीय हैं; अल्पसंख्यक और स्वदेशी समूह; जो लोग शरणार्थी, अप्रवासी या हैं प्रवासियों; जो लोग गरीब हैं; और यहां तक कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी। हम सभी को खड़े होकर जातिवाद, पूर्वाग्रह एवं अफवाहों का सामना करना चाहिए। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हमारा सन्दर्भ बिंदु होंगी।

- समर्थन, तैयारियों को मजबूत करना, खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु नागरिक संस्थाओं को दीर्घकालिक समाधान के लिए समुदायों के साथ सामूहिक चर्चा और योजना शुरू करने की आवश्यकता है। नागरिक संस्थाओं को सार्वभौमिक उत्थान के लिए राजनीतिक एवं व्यावसायिक समूहों के साथ कार्य करना होगा जिसमें खाद्य संप्रभुता एवं स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी करनी होगी।

आशाएं

आज के समय की चुनौतियों के बावजूद, नागरिक समाज की कार्रवाई में कोई कमी नहीं आई है। कई समुदायों में इस महामारी ने वास्तव में समूहों, परिवारों के बीच स्वेच्छाचारिता, मानवीय कार्य और आपसी सहयोग की भावना को बढ़ाया है। व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं के बीच मानवता की सेवा भावना उत्पन्न हुई है। इन नागरिकों के कार्यों का समर्थन, मार्गदर्शन और किया जाना चाहिए निरंतर, ताकि वे समाज मे वास्तव में परिवर्तनकारी शक्ति बन जाएं।

हमारी ओर से, कृषि सुधार के लिए एशियाई एनजीओ गठबंधन और ग्रामीण विकास (ANGOC) काम करना जारी रखेगा जिसमे अनुभव, सबक, नवाचार विचारों का आदान-प्रदान करते रहेंगे। हम खाद्य सुरक्षा, स्वतंत्रता, नौकरी और न्याय, भूमि और श्रम, शांति और वर्तमान और सफल पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुरक्षित करने का प्रयास अनवरत जारी रखेंगे।

एक कदम आगे बढ़ने पर, ANGOC नेटवर्क द्वारा खाद्य सुरक्षा का आकलन करने के लिए ठोस और समुदाय आधारित जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जिससे परिवार एवं समुदाय के स्तर पर योजना एवं गतिविधि निर्माण किया जा सकेगा।

हम स्थानीय खाद्य केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेंगे जिससे कि छोटे खाद्य उत्पादकों एवं उपभोक्ता के बीच की दूरी कम हो सके।

अंत में, हम अन्य संस्थाओं और नेटवर्क को बढ़ाने में कार्यरत हैं। इस कथन को प्रसारित करें और संवाद का निर्माण करें, एक दूसरे से सीखें, जिससे हम एक करुणामय बेहतर कल का निर्माण कर सकें।

ANGOC लोगों पर केंद्रित सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है
भोजन और स्वतंत्रता
काम और न्याय
भूमि और श्रम
शांति और समृद्धि
भोजन एक न्यूनतम, बुनियादी मानव अधिकार है लेकिन यह आजादी के बिना अर्थहीन है। स्वतंत्रता हमें याद दिलाती है कि हमारे प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्रता आज न केवल राजनीतिक पर केन्द्रित होना चाहिए लेकिन, आर्थिक यह रूप से भी स्वतन्त्रता का अवसर उतना ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में भोजन और स्वतंत्रता किसी भी समुदाय के मूलभूत अधिकार हैं।

यहां स्वतंत्रता का एक विशिष्ट एशियाई मूल्य मौजूद है - सभी के लिए नैतिकता का जीवित होना, अतीत की साझा गरीबी से भविष्य की साझा समृद्धि की ओर का पथ।

विश्व व्यापार उदारीकरण के प्रभाव और भूमंडलीकरण से वैश्वीकरण ने भी तेजी से वृद्धि की है जिसके फलस्वरूप एशिया की विशाल और विविध भूमि और जल संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए, एशियाई गैर सरकारी संगठन द्वारा - तेजी से सक्रिय प्रतिभागियों में पर्यावरण आंदोलन - को जारी रखना चाहिए।

अब के लिए सार्वभौमिक चिंता व्यक्त करते हैं पारिस्थितिक सामंजस्य। कई एशियाई किसानों को जमीन तक जारी है उनका अपना नहीं है; प्रचलित कृषि बंधे हुए में बचे हुए ढांचे श्रम। इसलिए, की आवश्यकता है व्यापक कृषि सुधार करने के लिए हार्नेस सभी के लाभ के लिए भूमि और श्रम।

अंत में, उदारीकरण के इस युग में युद्ध और जातीय संघर्ष, हमें याद दिलाते हैं सम्मान के साथ क्षमादान और शांति के साथ गरिमा की। जैसे बिना शांति विकास नहीं हो सकता वैसे ही समृद्धि भी बिना शांति असंभव है।

हस्ताक्षर
एशियन एनजीओ कोएलिशन फ़ॉर एग्रेरियन रिफॉर्म एंड रूरल डेवलपमेंट
एसोसिएशन फ़ॉर लैंड रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट
कम्युनिटी डेवेलपमेंट असिस्टेंस
कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस सेंटर
कोसोर्सियम प्रेमबरुआन अग्ररिया
एनजीओ फेडरेशन ऑफ नेपाल
साउथ एशिया रूरल रिकॉन्सट्रक्शन एसोसिएशन

स्टार कंपूचिया
एकता परिषद

8 September 2020

For those interested in signing on to this Statement in the spirit of solidarity, kindly inform the ANGOC Regional Secretariat at angoc@angoc.org.

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)
33 Mapagsangguni Street, Sikatuna Village, Diliman
1101 Quezon City, Philippines
angoc@angoc.org
+63 2 83510581
+63 2 83510011